पुलिस पर भरोसा नहीं सीबीआई जांच हो

एमबीबीएस छात्रा की मौत का मामला ध्यानाकर्षण में उठा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 23 फरवरी. गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में बीते 10 फरवरी को एमबीबीएस की छात्रा रोशनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सोमवार को सदन में ध्यानाकर्षण के दौरान उठा. ये मामला कांग्रेस सदस्य श्रीमती सेना महेश पटेल और राजन मंडलोई ने उठाया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले को लेकर पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए या तो न्यायिक जांच हो या फिर सीबीआई की जांच हो.

ध्यानाकर्षण में सदस्य श्रीमती सेना पटेल ने आरोप लगाया कि छात्रा हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, लेकिन उसका शव तीसरी मंजिल पर मिला. मृतका के मुंह पर चोट के निशान थे. उन्होंने कहा कि मृत्यु की सूचना परिवारजनों को समय पर नहीं दी गई और पोर्स्टमार्टम भी बिना उनकी अनुपस्थिति के करा दिया गया. उन्होंने मामले की सीबीआई से जांच नहीं होने पर समाज द्वारा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी. इस पर राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने कहा कि पीएम के समय उनकी माताजी मौजूद थीं. मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जिसमें तीन महिला पुलिस अफसरों को शामिल किया गया है. उन्होंने मृत्यु के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई के दबाव को जिम्मेदार बताया. राज्य मंत्री ने कहा कि एसआईटी निष्पक्षता से जांच कर रही है. वहीं सदस्य राजन मंडलोई ने मौत के लिए जातिगत भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना को जिम्मेदार बताया. उन्होंने सवाल उठाया कि बच्चों का काउंसलिंग क्यों नहीं की गई? पुलिस ने शुरू से ही मामले को आत्महत्या मान लिया. हमें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, मामले की न्यायिक जांच हो या फिर सीबीआई की जांच हो. वहीं ध्यानाकर्षण में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पढ़ने में मेधावी बच्ची आत्महत्या कैसे कर सकती है. शरीर पर नीले निशाने मिले हैं. उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, तथ्य छिपाया जा रहा है. उनके माता-पिता सबेरे मेरे घर आये थे, वे रो रहे थे.

अनुपूरक बजट पारित

सदन में सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए तृतीय अनुपूरक बजट को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि अनुपूरक का 10353 करोड़ रुपए पूंजीगत मद में खर्च होंगे. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे और रोजगार बढ़ेगा. अनुपूरक बजट में कई नई योजनाएं भी है, जिसके लिए राशि का प्रावधान किया गया है. देवड़ा के जवाब के बाद अनुपूरक को पारित कर दिया गया. इससे पहले चर्चा में सत्ता पक्ष की ओर से गौरव पारधी और विपक्ष कीओर से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हिस्सा लिया.

सीएम से जुड़े विभागों की अनुदान मांगें पारित

सदन में सोमवार से वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर विभागवार चर्चा की शुरुआत हुई. सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जुड़े विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, चर्चा के बाद सामान्य प्रशासन,, विमानन, गृह, पर्यावरण, जेल, वन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, लोक सेवा प्रबंधन, खनिज साधन, विधि एवं विधायी कार्य , जनसंपर्क,प्रवासी भारतीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,नर्मदा घाटी विकास और आनंद विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.

हलाली डैम के समीप 5 गिद्धों को छोड़ा

रायसेन, 23 फरवरी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा सोमवार को रायसेन जिले में हलाली डैम के समीप 05 गिद्धों को प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। इनमें चार भारतीय गिद्ध (जिप्स इंडिकस) और एक सिनेरियस गिद्ध (एजिपीयस मोनाकस) शामिल हैं। प्राकृतिक वातावरण में छोड़े गए गिद्धों पर जीपीएस ट्रैकर लगाए गए हैं, जिससे उनके आवागमन, व्यवहार एवं सुरक्षा की सतत निगरानी सुनिश्चित की जा सके। उच्च परिशुद्धता वाले जीपीएस-जीएसएम उपग्रह ट्रांसमीटरों से सुसज्जित पाँच दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों को भोपाल स्थित गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र में व्यवस्थित अनुकूलन और अवलोकन अवधि के बाद मुक्त किया गया है।

अमरीकी डील से व्यापारी भी होंगे प्रभावित

विशेष संवाददाता

भोपाल, 23 फरवरी. मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने सोमवार को श्यामला हिल्स और लखेरापुरा चौक बाजार में प्रमुख व्यापारियों से मुलाकात कर प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर चर्चा की.

> समझौते को लेकर हरीश चौधरी ने की चर्चा

व्यापार समुदाय को संबोधित करते हुए हरीश चौधरी ने कहा कि यह डील केवल किसानों ही नहीं, बल्कि व्यापार, उद्योग और रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगी. उन्होंने चेतावनी दी कि सोयाबीन, मक्का और सरसों जैसे प्रमुख कृषि क्षेत्र इसके दूरगामी परिणाम भुगतेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि मक्का के भूसे के आयात की अनुमति दे दी गई है और सोयाबीन तेल पर लगने वाला 16 प्रतिशत सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जिससे घरेलू प्रसंस्करण उद्योगों पर संकट गहरा जाएगा. उन्होंने कहा कि देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाले कपास और टेक्सटाइल क्षेत्र पर भी इसका गंभीर असर पड़ेगा. राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने आशंका जताई कि इस समझौते के तहत संवेदनशील आंकड़े विदेशों में उजागर हो सकते हैं. साथ ही, ईरान और रूस से तेल आयात को लेकर दबाव से आर्थिक नुकसान की भी चेतावनी दी.

सीएम हेल्पलाइन पर 19 हजार 314 शिकायतें पेंडिंग

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 23 फरवरी. राजधानी भोपाल में सोमवार को सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों को लेकर बैठक आयोजित की गई.पेंडिंग शिकायतों को अधिकारी निपटाने को लेकर गंभीर नहीं है. जिसके चलते शिकायतें महीनों तक पेंडिंग रहती हैं.

> पेंडेंसी वाले अधिकारियों को लगाई फटकार
>
> परानी जलाने से रोकने किसानों को जागरूक करें

कई बार इन शिकायतों को शिकायतकर्ता की जानकारी के बिना ही बंद कर दिया जाता है. इससे लोग दौबारा शिकायत करते हैं. वर्तमान में सीएम हेल्पलाइन पर 19 हजार 314 शिकायतें पेंडिंग हैं. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन पेंडेंसी पर जमकर फटकार लगाई. उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन में पेंडिंग शिकायतों को निपटाने में लग जाएं. सबसे पहले उन शिकायतों को तेजी से निपटाया जाए जो 50 दिन से अधिक समय से पेंडिंग हैं. यदि इन शिकायतों को निपटाने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जो शिकायतों को बिना देखे ही छोड़ा है या जिनका डिस्पोजल (निराकरण) संतोषजनक नहीं है, उन अधिकारियों पर भी तत्काल एक्शन लेने के निर्देश कलेक्टर ने जारी कर दिए. बैठक में जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी, एडीएम सुमित पांडे, अंकुर मेश्राम, प्रकाश नायक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. मार्च-अप्रैल में गेंहू, चना की फसल कटाई को देखते हुए एसडीएम व कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को जागरूक करना होगा. इस दौरान अधिकारी गांव गांव जाकर किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान की जानकारी देंगे. पराली जलाने की जगह किसानों को रोटावेटर और हैप्पी सीडर का उपयोग करने के निर्देश दिए. राजस्व विभाग से जुड़े मामलों जैसे नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन की पेंडेंसी को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए. अभियान के लिए सभी एसडीएम और तहसीलदार अपने स्तर पर तैयारियां करें. नगर निगम के अधिकारियों को समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी के कार्य में गति लाने के लिए कहा गया जिससे हितग्राहियों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके.

एक नजर में

72 स्ट्रीट डॉग को पकड़कर नसबंदी केन्द्र भेजा

भोपाल. नगर निगम के डाग स्क्वाड के दलों ने सोमवार को जोन क्षेत्रों में स्ट्रीट डॉग को पकड़ने की कार्यवाही करते हुए 12 डॉगको कजलीखेड़ा स्थित एबीसी सेंटर भेजा जबकि 31 डॉग को आदमपुर तथा 29 डॉग को अरवलिया एबीसी सेंटर भेजने की कार्यवाही की।इस प्रकार निगम के डॉग स्क्वाड ने कुल 72डॉग को नसबंदी केन्द्रों में भेजा तथा नसबंदी उपरांत 62 डॉग को वापस छोड़ा गया।

11 मील चौराहा से हटाया अतिक्रमण

भोपाल. राजधानी में सोमवार को जिला प्रशासन और नगर गिनम ने अतिक्रमण हटाने की संयुक्त कार्रवाई की. यह कार्रवाई होशंगाबाद रोड ग्यारह मिल चौराहे पर की गई. यहां पर सड़क का चौड़ाकरण किया जाना है यह अतिक्रमण इस कार्य में बाधा बन रहा था. इस कार्रवाई में निगम के अतिक्रमण अमले ने 6 दुकानों के बाहर लगे अवैध शेड बुलडोजर द्वारा तोड़कर 3 गुमठी एवं 5 ठेलों के अतिक्रमणों को हटाकर आवागमन को सुगम बनाया.

102 जल के नमूने एकत्र किए

भोपाल. नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दलों ने सोमवार को शहर की झुग्गी बस्तियों पेयजल के नमूने लेने की कार्रवाई की. जिससे जल की शुद्धता की पहचान हो सके. इस तरह से 102 जल के नमूने लिए गए. इन नमूनों में गंध, रंग, स्वाद, रेसिडुअल क्लोरीन, पीएच, टरबीडिटी व बैक्टेरिया की जांच कराने शहर की 8 परीक्षण शालाओं में भेजे गए। निगम अमले ने शहर वहीं 39 स्थानों पर पाईप लाईनों के लीकेज भी सुधारे और सीएम हेल्प लाईन, महापौर हेल्प लाईन सहित अन्य प्राप्त शिकायतों में से 2 शिकायतों का निराकरण किया. निगम अमले ने अभी तक झुग्गी बस्ती क्षेत्रों के 4876 स्थानों सहित शहर में कुल 10536 जल के नमूने लेकर 08 परीक्षण शालाओं के माध्यम से जल की गुणवत्ता की जांच कराई साथ ही 2101 लीकेज सुधारे. निगम अमले ने वर्तमान तक 6462 सीवेज चेम्बरों की सफाई कराई।

ननि एवं तहसील बैरसिया के लिए मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 23 फरवरी. राजधानी भोपाल में सोमवार को जनगणना के कार्य को लेकर बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला जनगणना अधिकारी भुवन गुप्ता ने सही और कार्य को गति देने के लिए भारत जनगणना 2027 सुचारू रूप से संपादित कराये जाने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनगणना के लिए मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति की.

यह मास्टर ट्रेनर नगर निगम भोपाल तहसील हूजूर एवं कोलार में संबंधित विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे. जिन मास्टर ट्रेनर्स को नियुक्त कियागया है उनमें सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी बीआरसीसीसी कार्यालय जनपद शिक्षा केन्द्र फंदा पुराना शहर के लिए एवं मुकेश नापित, सहायक प्राध्यापक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय साइंस एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोलार एवं सिद्धांत जैन सहायक प्राध्यापक शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तहसील बैरसिया ग्रामीण एवं नगरीय को नियुक्त किए गए हैं. ये बैरसिया शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों को ट्रेनिंग उपलब्ध कराएंगे. जिला जनगणना अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि मास्टर ट्रेनर्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. ये ट्रेनर्स डेटा संकलन की बारीकियों से अवगत कराएंगे, ताकि जनगणना के दौरान किसी भी प्रकार की विसंगति न रहे. विशेषकर डिजिटल डेटा एंट्री और मोबाइल ऐप के माध्यम से होने वाले कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

नवीन निगम मुख्यालय में जल कार्य और जीएडी

नगर निगम के नवीन मुख्यालय में अब कार्यालय शिफ्ट होने लगे हैं. उसी क्रम में सोमवार को जलकार्य और जीएडी विभाग शिफ्ट हो गया है. वहीं, इन विभागों के अपर आयुक्त वरुण अवस्थी का कार्यालय भी पहुंच गया है, अवस्थी के पास स्वच्छ भारत मिशन, संस्थापन शाखा, पेंशन शाखा, यांत्रिकीय प्रकोष्ठ, यात्रिकीय योजना (स्पेशल प्रकोष्ठ) शिक्षा उपकर के निर्माण कार्य, मुख्यमंत्री अधोसंरबना, जन्म-मृत्यु शाखा, विवाह पंजीयन प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना सी.एम. हेल्पलाईन भी हैं जो आगामी दिनों में जल्द ही पहुंच जाएंगे. अपर आयुक्त मंगलवार से नवीन भवन में बैठेंगे.

इनका कहना है

आज से नवीन भवन में बैठना शुरू कर दिया है, कुछ विभाग शिफ्ट हो गये हैं, शेष बचे विभाग भी जल्द आ जाएंगे.

- वरुण अवस्थी
अपर आयुक्त
नगर निगम भोपाल

मजदूरों के बच्चों को भी मिलेगी स्कूटी : पटेल

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 23 फरवरी. प्रदेश में अब मजदूरों के ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई में बेहतर परफॉर्म करेंगे, उनको भी स्कूटी मिलेगी. ये

> पढ़ाई में करना होगा अच्छा प्रदर्शन

घोषणा सदन में सोमवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए की.

मंत्री के जवाब के बाद श्रम विभाग की 1335 करोड़ 72 लाख 96 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग की 29662 करोड़ 86 लाख 26 हजार रुपए और पंचायत विभाग की 10429 करोड़ 72 लाख 97 हजार रुपए की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इससे पहले चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय मजदूरों को संबल योजना का लाभ नहीं दिया गया. इस कारण डेढ़ वर्ष का बैकलॉग हो गया था. हमने इस वर्ष के बजट में 6 माह का बैकलॉग खत्म किया है. लेकिन अभी भी एक साल का बैकलॉग बचा है, इसे खत्म करने में समय लगेगा.

आवारा पशुओं को भेजा कांजी हाउस

भोपाल, 23 फरवरी. नगर निगम के गौवर्धन परियोजना शाखा के अमले ने सोमवार को आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई की. इस दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 36 पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस में भेजा व हाका पार्टी ने 35 पशुओं को सड़कों से हटाया. इस दौरान शहर में 6 घायल और बीमार पशुओं को पशु चिकित्सालय तथा 20 पशुओं को गौशाला भेजने की कार्यवाही की. यह कार्रवाई शहर के श्यामला हिल्स, पॉलीटेक्निक, राजभवन, लालपरेड, पुरानी विधानसभा, मंत्रालय, लालघाटी, स्टेट हैंगर, बरखेड़ी, शाहपुरा, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, अशोका गार्डन, भानपुर, करोंद, जम्बूरी मैदान, खजूरी क्षेत्र में की गई.

डिवाइडर से टकराकर वाहन पलटा

तीन मजदूरों की मौत

नरसिंहपुर 23 फरवरी. निर्माणाधीन ब्रिज के डिवाइडर से टकराकर पिकअप वाहन पलट गया. हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई जबकि 7 घायल हैं. 3 की हालत गंभीर है.

सूआतला थाना पुलिस के अनुसार, हादसा सोमवार को बरमान चौकी क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर हुआ. वाहन में कुल 10 मजदूर सवार थे. ये सभी छिंदवाड़ा जिले के सुरला खापा गांव निवासी बताए जा रहे हैं. वे नरसिंहपुर के राजमार्ग क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य के लिए जा रहे थे.

थाना प्रभारी प्रियंका केवट ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में वाहन का अनियंत्रित होना दुर्घटना की वजह माना जा रहा है. दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. एक घायल ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ा. हादसे में फूलवती (50) पति शंकर गोंडनारायण (55) पिता गोलू ठाकुर, खुर्सनिया बाई (50) पति नारायण ठाकुर, सुम्मी पति (40) झामु उइके, रतन सिंह ठाकुर घायल हुए हैं. बाकी दो घायलों और मृतकों की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है.

227 गौवंश को कराया मुक्त

> पशु क्रूरता के विरुद्ध राज्य व्यापी अभियान

विशेष संवाददाता

भोपाल 23 फरवरी. मध्य प्रदेश पुलिस ने अवैध गौवंश तस्करी और पशु क्रूरता के विरुद्ध चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान को तेज करते हुए पिछले दस दिनों में 227 गौवंश एवं अन्य पशुओं को मुक्त कराया है. समन्वित फील्ड कार्रवाई, तकनीकी निगरानी और अंतर-जिला सूचना तंत्र के माध्यम से पुलिस ने अवैध परिवहन में प्रयुक्त ट्रक, कंटेनर और पिकअप वाहन जब्त किए तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए हैं.

पन्ना जिले में देवेंद्रनगर पुलिस ने 32 गौवंश को मुक्त कर लगभग 25 लाख रुपये मूल्य का कंटेनर जब्त किया. मझगवां पुलिस ने 71 भैंसों को छुड़ाकर करीब 40 लाख रुपये मूल्य के दो ट्रक जब्त किए, जबकि मड़ला थाना पुलिस ने आठ पशुओं और एक पिकअप वाहन को बरामद किया. सीधी जिले के मझौली थाना पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक ट्रक से 53 भैंसों को मुक्त कराया. डिंडोरी, सिवनी, खरगोन, गुना, छिंदवाड़ा और उज्जैन जिलों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन जब्त किए गए. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पशु तस्करी के मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति जारी रहेगी और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर की जाएगी.

बैठक | सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय, प्रदेश, जिले स्तर पर टास्क फोर्स का गठन

छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बैठक आयोजित

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 23 फरवरी. राजधानी में छात्रों को मानसिक तनाव से मुक्त करने के लिए सोमवार को हमीदिया कॉलेज के प्रिंसिपल अनिल सिरवानी

> जिला स्तर पर टास्क फोर्स के सदस्यों को बढ़ाया जाएगा
>
> काउंसलर की मदद से प्रभावितों की होगी निगरानी

की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के स्कूल, कॉलेजों, स्वास्थ्य विभाग और अन्य शिक्षण संस्थानों के शिक्षकगण शामिल हुए.

टास्क फोर्स के गठन के बाद एक आत्महत्या

भोपाल में टास्क फोर्स के गठन के बाद हमीदिया अस्पताल में मेडिकल की छात्रा द्वारा मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या का पहला मामला है. इस तरह की घटना भविष्य में किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी छात्र के साथ ना हो इसके लिए अब टास्क फोर्स लगातार विजिट करेंगे.

इस बैठक में एमएलबी कॉलेज की मनोवैज्ञानिक विभाग की विभाग प्रमुख अनीता पुरी सिंह भी प्रमुख रुप से मौजूद रहीं. यह बैठक ऐसे अध्ययनरत छात्रों के लिए की गई जो पढ़ाई के दबाव के कारण अवसाद में रहने लगते हैं या फिर आत्महत्या जैसे कदम उठाने लग जाते हैं. उनके लिए मनाचिकित्सक के माध्यम से कांउसलिंग कर अवसाद जैसी बीमारी से निकालने पर चर्चा की गई.

हमीदिया कॉलेज के प्रिंसिपल अनिल सिरवानी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय, प्रदेश, जिले स्तर पर टास्क फोर्स का गठन पहले ही किया जा चुका है, जिले में इस फोर्स में 10 सदस्य हैं जो कि पर्याप्त नहीं हैं. क्योंकि राजधानी में शासकीय और निजी कॉलेजों को मिलाकर लगभग 100 कॉलेज है. साथ बड़ी तादाद स्कूल और कोचिंग सेंटर बने संचालित हैं. इसलिए टास्क फोर्स में सदस्य बढाने पर विचार किया गया है.

शिक्षण संस्थानों में जाकर करेंगे काउंसलिंग

सिरवानी ने बताया कि टास्क फोर्स कम से कम सप्ताह में एक दिन जाकर शहर के सभी संस्थानों में विजिट करेंगे. वहां के शिक्षकों और छात्रों से जानकारी लेंगे, अगर कोई छात्र इस बीमारी से ग्रस्त पाया जाता है या उसमें ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस छात्र से काउंसलिग कर मनौचिकित्सक उपचार करेंगे. और साथ ही काउंसलर उसे 24 घंटे अपनी निगरानी में रखेंगे. छात्रों के पालकों को मोबाईल और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने के लिए भी जानकारी दी जाएगी.

अवसाद के लक्षण

- सहपाठी से दूरी बनाने लगे
- किताबें फैंकने या फाड़ने लगे
- किताबें किसी को बांटने लगे
- आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लगे
- घर में अकेला रहने लगे
- चिड़चिड़ापन दिखाई देने लगे

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री तुलसी राम सुश्री रानी लोधी डेरी (प्रॉस्पेक्ट नं. आई10598487)	ख.नं. 49, पीएचएन 96, क्षेत्रफल 1200 वर्गफुट ग्राम बखेड़ा, तहसील और जिला- विदिशा, मध्य प्रदेश, भारत, पिन 464001 क्षेत्रफल (वर्गफुट में) संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल क्षेत्रफल- 1200.00, 250.00, 362.00	रु. 204512/- (रु. दो लाख चार हजार पांच सौ बारह मात्र)	06-10-2025	19/02/2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: 183, प्रथम तल, सोनी भवन, एम.पी. नगर, जोन-2, भोपाल /या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- भोपाल, दिनांक- 24/2/2026 **प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**